सूर्य कांत और आर.पी. नागरथ न्यायमूर्ति के समक्ष

अशोक चोपड़ा- -*अपीलार्थी*

बनाम

मीना चोपड़ा व अन्य *उत्तरदाता*

एफएओ 2011 की सं. 2942

अप्रैल 23, 2013

हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 - कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 - धारा 10 - सिविल प्रक्रिया न्यायालय संहिता, 1908 - धारा 16, 21 - पत्नी और बच्चों ने भरण-पोषण के लिए हिसार में वाद दायर किया और पति/पिता से संबंधित जींद में अचल संपत्ति पर प्रभार सृजित किया - परिवार न्यायालय हिसार ने वाद की डिक्री की और अचल संपत्ति पर आरोप बनाया - पति ने मुख्य आपत्ति उठाई कि अचल संपत्ति के संबंध में हिसार में कुटुंब न्यायालय द्वारा अचल संपत्ति पर प्रभार बनाया गया जींद में क्षेत्राधिकार के बिना है - यह माना गया कि कोई पूर्वाग्रह नहीं दिखाया गया है, खासकर जब हिसार में फैमिली कोर्ट के पास रखरखाव का फैसला करने और अनुदान देने का अधिकार क्षेत्र है - अपील खारिज कर दी गई।

अभिनिर्धारित किया कि कूपिलान उनीन की बेटी पथुम्मा और अन्य बनाम कूपिलानअनकन के बेटे कुंतलन कुट्टी (मृतक) की एलआर और अन्य द्वारा, (1981) 3 एससीसी 589 में सी.पी.सी. की धारा 21 की व्याख्या करते समय यह देखा गया कि अपीलीय न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा मुकदमा करने के स्थान पर आपत्ति पर विचार किया जा सकता है, निम्नलिखित तीन शर्तों की पूर्ति आवश्यक है

"(i) आपत्ति प्रथम दृष्टया न्यायालय में ली गई थी।

(ii) इसे यथाशीघ्र अवसर पर लिया गया था और ऐसे मामलों में जहां मुद्दों का निपटान हो गया था, ऐसे निपटान पर या उससे पहले।

(iii) इसके परिणामस्वरूप न्याय विफल रहा है।

आगे अभिनिर्धारित किया कि इन सभी स्थितियों का सह-अस्तित्व होना चाहिए।

(*पैरा* 11)

अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता के वकील कोई पूर्वाग्रह या न्याय की विफलता दिखाने में सक्षम नहीं हुए हैं यदि हिसार में फैमिली कोर्ट ने जींद में स्थित अचल संपत्ति पर आरोप लगाने का आदेश दिया है, खासकर जब हिसार में फैमिली कोर्ट के पास निर्विवाद रूप से रखरखाव के मुकदमे का फैसला करने और डब्ल्यूआईएफसी और नाबालिग बच्चों के लिए रखरखाव भत्ता देने का अधिकार क्षेत्र था।

(*पैरा* 12)

सुधीर मित्तल, *अपीलकर्ता के वकील*

वी, के, संधीर, *उत्तरदाताओं के लिए वकील*

आर.पी. नागरथ न्यायमूर्ति

अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 का विवाह 26.08.1997 को संपन्न हुआ था। प्रतिवादी नंबर 2 और 3, विवाह से पैदा हुए नाबालिग बच्चे, अपनी मां की देखभाल और कस्टडी में रहते हैं। दंपति के बीच वैवाहिक विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके कारण सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण याचिका दायर की गई और आईपीसी की धारा 498-ए, 406 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही में अंतरिम रखरखाव प्रदान किया गया था, जिसमें अपीलकर्ता को प्रत्येक प्रतिवादी को 400/- रुपये प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

(2) प्रतिवादियों ने हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956 के तहत परिवार न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें उनमें से प्रत्येक को 4000/- प्रति माह पर रखरखाव का दावा किया गया और अचल संपत्तियों पर प्रभार बनाने के लिए क्योंकि उत्तरदाताओं ने आशंका व्यक्त की कि इन संपत्तियों को रखरखाव लागू करने से वंचित करने के लिए बेचा जाएगा। परिवार ने प्रतिवादियों में से प्रत्येक को भरण-पोषण भत्ता के रूप में 1500/- प्रति माह प्रदान करते हुए वाद की डिक्री की और आगे यह कि वे Ex.P-I और Ex. P-3 में उल्लिखित अचल संपत्तियों पर प्रभार बनाकर रखरखाव राशि की वसूली के हकदार हैं, जो वर्ष 2005-06 के लिए 1 हाउस टैक्स असेसमेंट रजिस्टर की प्रतियां हैं।

(3) प्रतिवादी-पति ने फैमिली कोर्ट हिसार द्वारा पारित फैसले और डिक्री को चुनौती देने के लिए इस अपील को प्राथमिकता दी, जहां प्रतिवादी वादी रह रहे हैं। जब 07.09.2012 को तत्काल अपील की गई, तो निम्नलिखित आदेश पारित किया गया: -

"सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने डिक्री पर इस हद तक विवाद नहीं किया कि प्रतिवादी को रखरखाव का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। हालांकि,

उन्होंने रखरखाव के भुगतान के लिए शुल्क के सृजन के बारे में गंभीर आपत्ति जताई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट रखरखाव के भुगतान के लिए शुल्क बनाने का आदेश नहीं दे सकता था। हाउस टैक्स असेसमेंट रजिस्टर (Ex. P-1) पर रखी गई निर्भरता जिसमें ओल्ड टाउनशिप, जींद में स्थित संपत्ति 455/9 और उसमें उल्लिखित संपत्ति से संबंधित मूल्यांकन रजिस्टर (Ex. P-3), जो वास्तव में अपीलकर्ता के पिता के नाम पर है, को आरोप के निर्माण के अधीन नहीं किया जा सकता था। यह प्रस्तुत किया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 16 के मद्देनजर, विद्वान ट्रायल कोर्ट के पास उक्त संपत्तियों पर आरोप लगाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था जो जींद में स्थित हैं और मुकदमा हिसार में दायर किया गया था। इसके अलावा, पूर्व पी-1 में उल्लिखित संपत्ति को 04.08.2006 को बिक्री विलेख (अनुबंध ए-1) के तहत बेचा गया था, जिसे हालांकि, ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया गया था और 21.07.2006 को मुकदमा दायर करने के बाद निष्पादित किया गया था। वह हालांकि, किसी अन्य उचित के संबंध में निर्देश लेने के लिए समय की प्रार्थना करता है जो रखरखाव के भुगतान को सुरक्षित करने के लिए दिया जा सकता है।

अपीलकर्ता ने उपरोक्त टिप्पणियों पर कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की।

(4) अपीलकर्ता ने डिक्री के ऊपर चर्चा के अनुसार रखरखाव की मात्रा पर विवाद नहीं किया है, इस छोटे से आधार पर पुष्टि की जाती है। एकमात्र प्रश्न जो विचार के लिए जीवित है वह यह है कि क्या जींद में स्थित अचल संपत्ति के संबंध में हिसार में परिवार न्यायालय द्वारा अचल संपत्ति पर प्रभार का सृजन अधिकार क्षेत्र के बिना है।

(5) हमने रिकॉर्ड मंगाए हैं, इसका अवलोकन किया है और पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है।

(6) निचली अदालत के समक्ष अपीलकर्ता के लिखित बयान में प्रारंभिक आपत्ति ली गई थी कि हिसार में सिविल कोर्ट को वर्तमान मुकदमे पर विचार करने और मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। निचली अदालत द्वारा निपटाए गए मुद्दों को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जाता है: -

i. क्या वादी को वर्ष 2005-06 के लिए हाउस टैक्स असेसमेंट रजिस्टर के अनुसार वाणिज्यिक संपत्ति नंबर 459/9 और नंबर 579/10 के साथ-साथ नंबर 530/9 पर शुल्क वसूलने के साथ-साथ प्रति माह 4,000 रुपये की वसूली करने का अधिकार है, जैसा कि वाद में आरोप लगाया गया है? ओपीपी

ii. क्या वादी का वाद विचारणीय नहीं है? ओपीडी

iii. क्या वादी ने अदालत से भौतिक तथ्यों को दबा दिया है? ओपीडी

iv. मदद

(7) तैयार किए गए मुद्दों से यह स्पष्ट है कि निचली अदालत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी की दलील पर जोर नहीं दिया गया था। अपीलकर्ता ने भी इस मुद्दे को बाद में या यहां तक कि बहस के स्तर पर, परिवार न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया। अपीलकर्ता ने किस पूर्वाग्रह का सामना किया है, यह प्रदर्शित नहीं किया गया है।

(8) तत्काल अपील में अपीलकर्ता का दूसरा तर्क यह है कि दुकान को निचली अदालत में सम्मन दिए जाने से पहले ही 04.08.2006 के सेल डीड के तहत बेच दिया गया था। यह मुकदमा 21-07-2006 को शुरू किया गया था। यदि अपीलकर्ता ने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान इस दुकान को बेच दिया था, तो वह कोई शिकायत नहीं उठा सकता है। यह क्रेता है जो अदालत में आ सकता है और इस तरह के मुद्दे को उठा सकता है। दूसरी संपत्ति अपीलकर्ता के पिता के नाम पर बताई गई है और यह तर्क दिया गया है कि संपत्ति के प्रकृति में पैतृक होने का कोई सबूत नहीं है, इस आधार पर अपीलकर्ता को कोई शिकायत नहीं हो सकती है और केवल आरोप के निर्माण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित लोगों के पास एक अलग उपाय हो सकता है।

(9) विद्वान अपीलकर्ता के वकील ने जोरदार तर्क दिया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 10 के आधार पर फैमिली कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर लागू होंगे, यह प्रस्तुत किया गया है कि संहिता की धारा 16 अचल संपत्ति के संबंध में मुकदमा करने की जगह प्रदान करती है। यह आगे आग्रह किया गया है कि अचल संपत्ति पर प्रभार के निर्माण पर इसे जीवन भर के लिए निपटाया नहीं जा सकता है, भले ही अपीलकर्ता ने रखरखाव के बकाया जमा कर दिए हों और बिना किसी चूक के हर महीने ऐसा करना जारी रखेगा। दूसरी ओर, प्रतिवादियों के वकील ने प्रस्तुत किया कि वह उपरोक्त बयान को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि उनके अनुसार पिछले लगभग एक वर्ष से रखरखाव की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। तात्कालिक अपील में इस विवाद में जाने की जरूरत नहीं है। रखरखाव की वसूली के लिए प्रभार बनाने का परिणाम केवल यह है कि जब भी संपत्ति का निपटान किया जाता है, लेनदेन हमेशा रखरखाव की वसूली के लिए बनाए गए शुल्क के अधीन होगा। वास्तव में, प्रतिवादी-पत्नी की आशंका काल्पनिक नहीं थी, क्योंकि मुकदमा दायर करने के दो सप्ताह के भीतर ही एक संपत्ति बेच दी गई थी।

(10) अचल संपत्ति पर आरोप बनाने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के मुद्दे पर आते हुए, विद्वान अपीलकर्ता के वकील ने *हर्षद चिमन लाल मोदी* बनाम *डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड और अन्य* (1981) 7 एससीसी 791 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। थाल अचल संपत्ति को बेचने के लिए एक समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमा था जो

स्पष्ट रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 16 के दायरे में आता है और सिविल कोर्ट के समक्ष रखता है, जहां विषय वस्तु स्थित थी। यह निर्णय इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

(11) कूपिलान उनीन की बेटी पथुम्मा और अन्य बनाम कूपिलान उनीन के बेटे कुंतलन कुट्टी में एलआर और अन्य द्वारा मृत, सीपीसी की धारा 21 की व्याख्या करते समय यह देखा गया था कि अपीलीय अदालत या पुनरीक्षण अदालत द्वारा मुकदमा करने के स्थान पर आपत्ति पर विचार किया जा सकता है, निम्नलिखित तीन शर्तों की पूर्ति आवश्यक है:

"(i) आपत्ति प्रथम दृष्टया न्यायालय में ली गई थी।

(ii) इसे यथाशीघ्र अवसर पर लिया गया था और ऐसे मामलों में जहां मुद्दों का निपटान हो गया था, ऐसे निपटान पर या उससे पहले।

(iii) इसके परिणामस्वरूप न्याय विफल रहा है।

आगे अभिनिर्धारित किया कि इन सभी स्थितियों का सह-अस्तित्व होना चाहिए।

(12) अपीलकर्ता के वकील किसी भी पूर्वाग्रह या न्याय की विफलता दिखाने में सक्षम नहीं हैं यदि फैमिली कोर्ट अल हिसार ने जींद में स्थित अचल संपत्ति पर आरोप लगाने का आदेश दिया है, खासकर जब हिसार में परिवार न्यायालय के पास निर्विवाद रूप से रखरखाव के मुकदमे का फैसला करने और पत्नी और नाबालिग बच्चों के लिए रखरखाव भत्ता देने का अधिकार क्षेत्र था।

(13) हमें अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती है, जिसे खारिज कर दिया जाता है।

ए. जैन

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

खुश करण जोत सिंह गिल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी